दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, गुरुवार 14 दिसम्बर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-77

कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री!

ऐलान अभी बाकी

नई दिल्ली (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। कमलनाथ के नाम की घोषणा खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों की मानें तो इसकी औपचारिक घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभा ओझा का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर छोड़ा गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से आज रात ही सरकार का दावा पेश करने को लेकर समय मांगा है। पार्टी ने इस संबंध में ईमेल और फैक्स भी भेजा है। इससे यह साबित होता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेता कौन होगा उसका निर्णय कांग्रेस ने कर लिया है। इधर जयोतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया है कि उन्हें केन्द्रीय नेतृत्व का फैसला स्वीकार्य है।

मसलन ऐसी खबर है कि कमलनाथ को

मध्य प्रदेश विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कहा जा रहा है कि उनके नाम पर औपचारिक मुहर राहुल गांधी लगाएंगे। हालांकि इस खबर की किसी ने भी पुष्टि नहीं की है लेकिन खबर में दम है कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ फिलहाल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद है। कमलनाथ यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायक दल की बैठक में खुद कमलनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उनके नाम पर सहमति बन है।

इधर राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम पर गहमा-गहमी जारी है। साथ छत्तीसगढ में भी मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा है।

वर्तमान जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें राज्य की सेवा का मौका दिया। इन राज्यों में बीजेपी सरकारों ने लोगों की भलाई के लिए जीतोड़ मेहनत की है।

कर्जमाफीः नई सरकार का खौफ या नजरों में चढ़ने की कवायद

न सरकार बनी, न कैबिनेट में निर्णय हुआ अधिकारी बैंकों से मांगे कर्ज के आंकड़े

रायपुर (आरएनएस)। भाजपा सरकार के जाते ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सहकारिता विभाग ने बैंकर्स कंपनी और मार्कफेड को पत्र लिख कर कर्जदार किसानों की सूची मांगी है। यह अधिकारियों में आने वाली सरकार का खौफ है या सरकार के नर में चढ़ने की कवायद है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक तिकड़म का हिस्सा मान रहे है। न तो सरकार का गठन हुआ है और न ही कैबिनेट में कर्जमाफी को लेकर कोई निर्णय हुआ है, फिर सहकारिता विभाग का अलर्टनेस क्या संदेश देता है। आने वाली सरकार पहले कैबिनेट बुलाएगी फिर प्रस्ताव लाएगी उसेक बाद समस्त विभागों को सूचना जाएगी। सरकार गठन से पहले विभाग का अलर्टनेस काबिले तारीफ है। या फिर भाजपा सरकार ही तरह सरकार की नजर में चढ़ने की कवायद है।

कर्जमाफी को लेकर कदम बढ़ा दिए

सरकार गठन की प्रकिया शुरु होते ही प्रशासन ने भी कांग्रेस की घोषणा के मुताबिक कर्जमाफी को लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा काफी मजबूती से उठाया था। वादा ये किया गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। सहकारिता विभाग ने पत्र जारी कर कर्ज को लेकर रिकार्ड मांगे हैं। बुधवार को सहकारिता विभाग के उप सचिव पीएस सर्पराज ने संचालक संस्थागत वित्त, बैंकर्स कमेटी और एमडी मार्कफेड को पत्र जारी किया है। इसमें कहा है कि कांग्रेस की घोषणा पूरी करने किसानों की ऋण माफी योजना तैयार किया जाना है।

बैंकों के 7 हजार करोड़ रुपए कर्जदार हैं किसान

सहकारिता विभाग को बैंकों ने 30 नवंबर 18 की स्थिति आप के अधीन कार्यरत बैंकों द्वारा किसानों को वितरित कृषि ऋ ण और उसके बकाए की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक साल के कर्ज को माफ करने का वादा किया है। बैंकर्स सूत्रों के अनुसार राज्य के करीब 34 लाख किसान सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से लगभग 7 हजार करोड़ कर्जदार हैं। इनमें से करीब 3900 करोड़ सहकारी बैंकों के है। हालांकि राज्य में इस कर्ज की भरपाई का औसत बेहतर हैं। किसान 90 फीसदी कर्ज का भुगतान करते रहे हैं। किसान या तो नकद या फिर धान को लिंकिंग में बेचकर कर्ज चुकाते हैं।

नए प्रमुख सचिव और डीजीपी की तलाश

कांग्रेस की सरकार गठन के साथ नए प्रमुख सचिव और डीजीपी बनाए जाएंगे। अंदर की खबर है कि हाईकमान ने जनता को भयमुक्त प्रशासन देने के वादे के अनुरूप कड़क प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य सचिव और डीजीपी बना सकती है।

विवादित बयान पर योगी की बढ़ी मुश्किलें

हनुमान भक्त अधिवक्ताओं ने कराया मामला दर्ज

नई दिल्ली (आरएनएस)। हनुमान पर विवादित बयान देने के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधियों के निशाने पर हैं। इस बीच खबर आयी है कि योगी के खिलाफ दिल्ली के एक न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि 27 नवंबर को राजस्थान के अलवर में रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी के लिए वंचित दलित शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर पूरे देश में खूब बवाल मचा।

पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट में विवादित बयान देने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई के लिए वकीलों ने शिकायत दी है। इस मामले में मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नायक ने चार जनवरी को कोर्ट में फर्श बाजार थानाध्यक्ष से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

हनुमान जी वाले बयान के बाद सैकड़ों हनुमान भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचने का दावा किया गया है। जिस कारण अधिवक्ता विजेता शर्मा, गीता तोमर व रविंदर शर्मा ने मिलकर डीसीपी व फर्श बाजार थाने में इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट नंबर 38 में मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नागर के समक्ष इस मामले पर कार्यवाही के लिए शिकायत की। अधिवक्ता विजेता शर्मा ने बताया कि योगी आदित्यनाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा इस तरह के बयान देना बिल्कुल उचित नहीं है। वह लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में उनका यह बयान देना शोभा नहीं देता। इसके विरोध में कनाट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रदशज्न भी किया। यहां पर बता दें कि सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवान हनुमान को दलित जाति का कहने को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग करते हुए जयपुर की एक निचली अदालत में याचिका दाखिल की है।

रायपुर- साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण, तैयारी शुरु

रायपुर। रायपुर के साइंस कॉलेज में कांग्रेस मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारी चल रही है. शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसम्बर को होना है. इससे पहले ही साइंस कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह का जायजा लेने एसपी अमरेश मिश्र पहुंचे हुए है. जहां वो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बैठने तक का जायजा ले रहे हैं. वहीं मुख्य सचिव अजय सिंह शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 3 बजे सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के हत्यारों को दो हफ्तों में फांसी देने से किया इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। साल 2012 में 16-17 दिसंबर की दरम्यिानी रात राजधानी दिल्ली में कुछ दरिंदों ने एक नाबालिग निर्भया के साथ गैंगरेप किया था, जिसके बाद पूरा देश निर्भया के हक में इंसाफ के लिए एकजुट हो गया था। वहीं इस मामले में 6 साल बीत जाने के बाद भी दोषियों को फांसी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के हत्यारों को दो हफ्तों में फांसी देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका डाली गई थी। याचिका में कहा गया था कि निर्भया के दोषियों को दो हफ्ते में फांसी दी जानी चाहिए। देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड के तीन गुनहगारों को दो हफ्तों के अंदर मौत की सजा दिलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वह केंद्र सरकार को आदेश दे कि वह निर्भया के गुनहगारों को दो सप्ताह के अंदर फांसी दे।

पीएम मोदी ने किया चौथे भागीदारी मंच 2018 का उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चौथे भागीदारी मंच (पार्टनर्स फॉरम) का उद्घाटन किया। फोरम में 85 देशों के लगभग 1,500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय फोरम का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों व किशोरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, भारत उन पहले देशों में शामिल है, जो किशोरावस्था पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है और किशोरों के लिए सघन स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम कार्यक्रम लागू किया है।

उन्होंने कहा कि नागरिकों, समुदायों और देशों के बीच सहभागिता से हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि भारत कौशल निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अपने साथी देशों केविकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा हमने बीते कुछ सालों में काफी कुछ हासिल किया है और अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना है।

उन्होंने कहा, मुझे यह जानकार प्रसन्नता हुई कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को इस फोरम में भारत की सफलता के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह विषय मेरे दिल के काफी करीब है। मिशन इंद्रधनुष के जरिए हम बीते तीन वर्षों में 3.28 करोड़ बच्चों और 84 लाख गर्भवती महिलाओं तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, हमने सर्वव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीकों की संख्या बढ़ाकर सात से 12 की है। हमारे टीकों के दायरे में अब प्राणघातक रोग निमोनिया और डायरिया भी शामिल हैं।

यह दूसरी बार है, जब भारत भागीदारी फोरम की मेजबानी कर रहा है। भारत में अंतिम बार यह फोरम 2010 में आयोजित हुआ था। यह दो दिवसीय कांफ्रेंस केंद्र सरकार ने पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ (पीएमएनसीएच) के साथ मिलकर आयोजित किया है।

कावेरी सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्यसभा में हंगामा

नयी दिल्ली (आरएनएस)। कावेरी नदी पर बांध बनाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर अन्नाद्रमुक, द्रमुक सहित विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक गुरुवार को शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की आज 17वीं बरसी है। उच्च सदन की बैठक शुरू होते ही उस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें चार नोटिस मिले हैं जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आंध्रप्रदेश से जुड़े मुद्दों तथा अन्य सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा कराई जाएगी। नायडू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अन्नाद्रमुक के सदस्य कावेरी नदी पर बांध बनाए जाने के विरोध में नारे लगाते हुए आसन के समक्ष आ गए। द्रमुक के सदस्य भी यही मुद्दा उठाते हुए अपने स्थानों से आगे आ गए। वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए आसन के समक्ष आ गए। अन्य दलों के सदस्य अपने अपने स्थानों से ही अपने मुद्दे उठाने की कोशिश करते रहे। सभापति ने आसन के समक्ष आए सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने की अपील करते हुए कहा ''हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सदन चले।'' उन्होंने कहा ''आज ही, संसद हमले की 17वीं बरसी पर, हमले में जान गंवाने वालों को हमने श्रद्धांजलि दी है। उनके बलिदान को याद करते हुए सदन में कम से कम आज कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इससे गलत संदेश जाएगा।

श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार चौथे दिन भी बंद

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताजा बर्फबारी के कारण गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी बंद रहा। यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने यहां को बताया कि जोजिला दर्रे के दोनों तरफ ट्रक और तेल टैंकरों समेत बड़ी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। ताजा बर्फबारी के कारण सड़क मार्गो पर फिसलन की वजह से राजमार्ग को एहतियातन बंद रखा गया है। यातायात अधिकारी ने कहा, राजमार्ग पर विशेषकर ,गंदेरबल जिले के सोनमर्ग और जोजिला एवं मीनमर्ग के बीच बर्फ जमा होने के कारण फिसलन बहुत बढ़ गयी है।

सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, दो को घेरा

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के सोपोर में आज सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरु हो गई। इस मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी भी दो और आतंकी छुपे हुए है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरु कर दिया है। स्थानिय लोगों को घरों के अंदर रहने और खिड़की दरवाजे बंद रखने की हिदायत दी गई है। बता दें कि सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि जम्मू-कश्मीर के सोपोर सेक्टर में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं।

आतंकियों को पकड़ने के लिए जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में दो आतंकियों को मार गिराया है। फायरिंग की आवाज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी दो आतंकी छुपे हुए हैं जिन्हें पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण एवं खास

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच से बड़ा आदेश, 1 माह में प्रदेश भर के स्पीड ब्रेकरों को हटाने का दिया आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच से बड़ा आदेश, 1 माह में प्रदेश भर के स्पीड ब्रेकरों को हटाने का दिया बड़ा आदेश, 9 जनवरी 2019 को शपथपत्र में जवाब करना होगा पेश।

ट्रंप के पूर्व वकील को तीन साल की कैद

वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिका में मैनहट्टन की एक अदालत ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लंबे समय तक व्यक्तिगत वकील रहे माइकल कोहेन को तीन साल की कारावास की सजा सुनायी।

व्हाट्सऐप पर मंगेतर से मजाक करना पड़ा भारी

कोर्ट ने सुनाई 60 दिन जेल की सजा

अबु धाबी (आरएनएस)। व्हाट्सऐप पर किसी से मजाक करना कितना भारी पड़ सकता है इसका ताजा उदाहरण संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सामने आया है। यहां एक शख्स को व्हाट्सऐप पर अपनी मंगेतर से मजाक करने के एवज में 60 दिन जेल की सजा हुई है। दरअसल उक्त व्यक्ति ने मजाक में अपनी मंगेतर को इडियट कह दिया था। बस फिर क्या था, मंगेतर को यह अच्छा नहीं लगा और उसने अपने होने वाले पति के खिलाफ केस कर दिया।

वियतनाम में बाढ़ से 13 मरे, एक लापता

हनोई (आरएनएस)। वियतनाम में भारी बारिश के कारण आयी बाढ़ में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गयी है और एक लापता है।

ट्रेन हादसा होते बचा, मालगाडी दो भागो में बटी

कपलिंग टूटने से आधा घण्टा बाधित रहा रूट

फतेहपुर (आरएनएस)। एक और बडा रेल हादसा उस वक्त होते-होते बच गया जब जिले के करुशतिकला रेलवे स्टेशन के समीप अचानक मालगाडी कि कपलिंग टूट जाने से दो हिस्सो में बट गयी। इसकी सूचना पाते ही रेलवे के अधिकारी कर्मचारी पहुचकर निरीक्षण किया और प्रशासन जांच में जुट गया और लगभग तीस मिनट तक अपलाइन रूट बाधित रहा।

टायर फटने पर टेम्पो में जा भिड़ा ट्रक, पांच की मौत, 7 घायल

जौनपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक ने सवारी भरे टेम्पो को टक्कर दी, जिससे उसपर सवार महिला सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गयी और अन्य सात घायल हो गए।

अयोध्या विवाद सहित 1.12 लाख केस निपटाए

जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने रचा इतिहास

इलाहाबाद (आरएनएस)। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के फैसले से चर्चित इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने एक लाख 12 हजार मुकदमों का निपटारा कर इतिहास रचा है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति अग्रवाल अपने कार्यकाल में देश में सर्वाधिक मुकदमों का निपटारा करने वाले न्यायाधीश बन गए हैं. इनमें से 10 हजार 815 केस लखनऊ बेंच के शामिल हैं. इन मुकदमों में 1788 फैसले नजीर बने, जिन्हें पुस्तकों में प्रकाशित करने योग्य माना गया.